

भारत सरकार  
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय  
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 166

जिसका उत्तर सोमवार, 24 नवंबर, 2014 को दिया जाना है

भारी उद्योगों का विकास

166. श्री केशव प्रसाद मौर्य:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या इलाहाबाद जैसे क्षेत्रों में जहां आस-पास के क्षेत्रों में प्रचुर खनिज भंडार है, भारी उद्योगों और सार्वजनिक उद्यमों के विकास के लिए कोई योजना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार देश में बेहतर अवस्थिति लाभों और परिवहन सुविधाओं सहित इलाहाबाद में एक बड़ा औद्योगिक केन्द्र बनाने पर विचार कर रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री  
(श्री जी. एम. सिद्धेश्वर)

(क) और (ख): चूंकि उद्योग राज्य का विषय है, इसलिए भारी उद्योगों के विकास के लिए इस विभाग की कोई योजना नहीं है। भारी उद्योग विभाग की भूमिका इसे आबंटित किए गए केपिटल गुड्स और ऑटो सेक्टर के अतिरिक्त अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रशासन तक सीमित है।

(ग) और (घ): जी, नहीं। औद्योगिक केन्द्र बनाने का कार्य इस विभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

\*\*\*\*\*